

मुकदमों का विवरण

वाई. पी. लीले

वी.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और ओ. आर. एस.

(सिविल अपील 2023 की आई. डी. 1) 16 अगस्त, 2023

[विक्रम नाथ और अहसानउद्दीन अमानुल्लाह, जे. जे.] हेडनोट्स

विचार के लिए विषय: क्या उच्च न्यायालय ने या को स्पष्टीकरण लागू करने में कोई त्रुटि की है। XVII, आर. 2 सी. पी. सी. और इसके आधार पर यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक आवेदन यू/या। IX नियम 13 सी. पी. सी. बनाए रखने योग्य नहीं होगा क्योंकि प्रतिवादी की उपस्थिति को मुकदमे के निपटारे के समय दर्ज किया गया माना जाएगा।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-या को स्पष्टीकरण। XVII, आर. 2 और या। IX, आर. 13:

आयोजित किया गया: जिस स्तर पर वादी के साक्ष्य का नेतृत्व किया जा रहा था, प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा वापस ले लिया-ट्रायल कोर्ट ने यू/ओआर को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। XVII, आर. 2 प्रतिवादियों के खिलाफ सी. पी. सी. और एकतरफा मुकदमा घोषित किया गया-ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादियों के आवेदन की अनुमति दी। IX, r. 13- हालाँकि, उच्च न्यायालय ने यू/या आवेदन पर निर्णय लिया। IX नियम 13 सी. पी. सी. बनाए रखने योग्य नहीं होगा और यू/या XVII के तहत स्पष्टीकरण लागू किया जाएगा। आर. 2 सी. पी. सी.-या के लिए स्पष्टीकरण। XVII, आर. 2 तत्काल मामले में केवल तभी लागू किया जा सकता था जब वादी, अपना साक्ष्य या पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद, पेश होने में विफल रहा हो, अदालत मुकदमे का निपटारा करते समय अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकती थी-लेकिन, एक बार जब प्रतिवादी ने कोई सबूत नहीं दिया था, तो प्रतिवादी/अपीलार्थी के खिलाफ स्पष्टीकरण का आह्वान नहीं किया जा सकता था-उच्च न्यायालय ने या को स्पष्टीकरण लागू करने में त्रुटि की। XVII, आर. 2 सी. पी. सी. और इसके आधार पर एक आवेदन यू/या। IX, आर. 13 सी. पी. सी. बनाए रखने योग्य नहीं होगा क्योंकि प्रतिवादी की उपस्थिति को मुकदमे के निपटारे के समय दर्ज किया गया माना जाएगा-इस प्रकार, उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है-पक्षकारों को उचित अवसर देने के बाद, विशेष दीवानी मुकदमे को आगे बढ़ाने और अपने गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिए विचारण न्यायालय।

[परिच्छेद 4,5,6,7 और 20] 142 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 11 एस. सी. आर.

सिविल प्रक्रिया संहिता, **1908-या। XVII,आर. 2-**उस स्तर पर जब वादी के साक्ष्य का नेतृत्व किया जा रहा था, प्रतिवादियों के वकील ने अपना वकालतनामा वापस ले लिया- ट्रायल कोर्ट ने यू/या आगे बढ़ने का निर्देश दिया। **XVII,आर. 2** प्रतिवादियों के खिलाफ सी. पी. सी. और एकतरफा मुकदमा घोषित किया-स्वामित्व:

आयोजित किया गया:वास्तव में, एक बार जब अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा वापस ले लिया था, तो सामान्य रूप से, निचली अदालत को प्रतिवादियों को एक अन्य अधिवक्ता को शामिल करने के लिए नोटिस जारी करना चाहिए था, जो उसने नहीं किया और एकतरफा रूप से आगे बढ़ा-निचली अदालत ने ऐसा करने में त्रुटि की।[पैरा 21]

सिविल प्रक्रिया संहिता, **1908-या। XVII,आर. 2-**इसके तहत समझ में आता है:

आयोजित किया गया:जो बात स्पष्ट है वह यह है कि यू/ओर। XVII,आर. 2, न्यायालय किसी भी पक्ष के अनुपस्थित होने या दोनों पक्षों के अनुपस्थित होने के संबंध में आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ेगा-जबकि स्पष्टीकरण उस पक्ष और अकेले उस पक्ष की उपस्थिति दर्ज करने के लिए है, जिसने साक्ष्य या पर्याप्त साक्ष्य का नेतृत्व किया है और उसके बाद उपस्थित होने में विफल रहा है।[पैरा 19]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड बनाम मिराज विद्युत आपूर्ति कंपनी।

लि. ओआरएस। 2015 की सिविल रिट याचिका संख्या 1488-संदर्भित।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन शामिल हैं

सिविल अपीलिय न्यायनिर्णय:2015 के डब्ल्यू. पी. No.1488 में बंबई उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 27.06.2018 से 2023 की सिविल अपील No.5155।

रूप:

विनय नवारे, वरिष्ठ अधिवक्ता, सम्राट कृष्णराव शिंदे, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

अजीत भास्मे, वरिष्ठ अधिवक्ता, मुकेश कुमार पांडे, रजनीश कुमार सिंह, ए. भास्मे, संजय कुमार विसेन, आनंद लैंडगे, चंदर शेखर अशरी, अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणों के लिए।

143

वाई. पी. लीले बनाम महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का निर्णय/आदेश

विक्रम नाथ, जे।

अनुमति दी गई

2. अपीलार्थी मूल प्रतिवादी नं.5, जैसा कि 1988 के विशेष दीवानी मुकदमा संख्या 125 की शिकायत में वर्णित है।

3. वर्तमान अपील "महाराष्ट्र राज्य विद्युत" शीर्षक से 2015 की सिविल रिट याचिका संख्या 1488 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित 27.06.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश की शुद्धता पर जोर देती है।

बोर्ड बनाम मिराज इलेक्ट्रिक सप्लाय कंपनी लिमिटेड ", जिसके तहत याचिका दायर की गई थी

अनुमति देते हुए, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 1 के आदेश IX नियम 13 के तहत आवेदन की अनुमति देने वाले विचारण न्यायालय द्वारा पारित 30.09.2014 दिनांकित आदेश को दरकिनार कर दिया गया और एक्सपार्ट डिक्री को बनाए रखा गया।

4. अनावश्यक तथ्यों को दरकिनार करते हुए, महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड 2 ने विशेष सिविल सूट नं. सिविल न्यायाधीश के न्यायालय में 1988 का 125, सांगली में वरिष्ठ प्रभाग ने मिराज इलेक्ट्रिक सप्लाय कंपनी लिमिटेड 3 को प्रतिवादी सं। 1 और प्रतिवादी एन. ओ. एस. के रूप में इसके निदेशक। 2 से 6 रुपये की वसूली के लिए। 1,42,85,177.47-वाद की लागत के साथ और वाद प्रस्तुत करने की तारीख से उपरोक्त राशि की प्राप्ति तक प्रति वर्ष 18 प्रतिशत की दर से ब्याज के लिए आगे की प्रार्थना। प्रतिवादी पेश हुए और अपने लिखित बयान दिए। वादी के साक्ष्य का नेतृत्व किया जा रहा था और उस स्तर पर प्रतिवादियों के अधिवक्ता श्री। एम. बी. करमरकर ने अपना वकालतनामा वापस ले लिया। 112. उन्होंने गवाहों से जिरह भी नहीं की थी। निचली अदालत ने 04.12.2004 पर प्रतिवादियों के खिलाफ सी. पी. सी. के आदेश XVII नियम 2 के तहत मुकदमा चलाने का निर्देश दिया। इसके बाद विचारण न्यायालय वादी के साक्ष्य को दर्ज करने के लिए आगे बढ़ा और दिनांक 1 के निर्णय और आदेश के माध्यम से, मुकदमे को लागत के साथ समाप्त करने का आदेश दिया। निर्णय के कार्यात्मक भाग को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है: "सूट को लागत के साथ निर्धारित किया जाता है, जैसा कि नीचे दिया गया है:

1. प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से रु। 1,42,85,177.47 PSI (रु. एक करोड़, बयालीस लाख, अस्सी हजार,

1 संक्षेप में, "सी. पी. सी". 2 संक्षेप में, "एम. एस. ई. बी". 3 संक्षेप में, "एम. ई. एस. सी".

144

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

एक सौ सत्ताईस और सैंतालीस पैसे केवल) वादी बोर्ड M.S.E.B को।)वे रुपये की बकाया राशि पर प्रति वर्ष Rs.18% की दर से ब्याज का भुगतान करेंगे। 1, 0490032.36 Psi (रु. एक करोड़ चार लाख उन्नीस हजार बत्तीस और छत्तीस पैसे केवल) मुकदमे की तारीख से इसकी प्राप्ति तक।

2. तदनुसार आदेश तैयार किया जाए।”5. प्रतिवादियों को, एक्सपार्ट डिक्री के बारे में पता चलने पर, देर से आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन का नेतृत्व किया, जिसके साथ 21.09.2006 पर सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन था। ट्रायल कोर्ट ने 20.09.2010 दिनांकित आदेश के माध्यम से, सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत आवेदन को अनुमति दी, जिसमें स्पष्टीकरण को रुपये की लागत के कारण हुई देरी के लिए संतोषजनक माना गया। 3, 000/- प्रतिवादियों पर दस दिनों के भीतर जमा किया जाना है।

6. इसके बाद, ट्रायल कोर्ट ने 30.09.2014 दिनांकित आदेश के माध्यम से, आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत आवेदन को अनुमति दी, और 29.01.2005 दिनांकित एक्सपार्ट डिक्री को दरकिनार कर दिया। 1, 000/- और 1988 के विशेष सिविल सूट संख्या 125 को इसकी मूल संख्या में बहाल किया।

7. वादी-एमएसईबी ने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका को प्राथमिकता दी। उच्च न्यायालय ने दिनांक 12.01.2015 के विवादित आदेश द्वारा रिट याचिका को अनुमति दी, दिनांकित 30.09.2014 के आदेश को दरकिनार कर दिया। नतीजतन, प्रतिवादी-एम. एस. ई. बी. का मुकदमा समाप्त घोषित हो गया। याचिका को इस आधार पर स्वीकार किया गया था कि आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं होगा क्योंकि उच्च न्यायालय ने आदेश XVII नियम 2 सी. पी. सी. के तहत स्पष्टीकरण लागू किया था।

8. उसी से व्यथित, वर्तमान अपील को एम. एस. ई. बी. को प्रत्यर्थी नं.1, प्रतियोगी प्रत्यर्थी, और अन्य चार निदेशकों को भी प्रत्यर्थी एन. ओ. एस. के रूप में शामिल करना। 3 से 6 तक। इसने एम. ई. एस. सी. को प्रत्यर्थी नं. के रूप में भी शामिल किया। 2. इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीनता के दौरान किसी स्तर पर, प्रत्यर्थी एन. ओ. एस. 2 से 6 तक को 21.10.2019 दिनांकित आदेश के माध्यम से पक्षों की श्रृंखला से हटाने का निर्देश दिया गया था। हालाँकि बाद में, 15.09.2021 दिनांकित आदेश के अनुसार, प्रतिवादी संख्या 2 और 6 को पक्ष प्रत्यर्थीगणों के रूप में बहाल कर दिया गया। 9. यह उल्लेख करना सार्थक होगा कि अपील को निदेशकों में से एक द्वारा प्राथमिकता दी गई है, जैसा कि शुरुआत में उल्लेख किया गया है, प्रतिवादी नं.5 विचारण न्यायालय के समक्ष।

10. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

11. अपीलार्थी के लिए विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि उच्च न्यायालय ने आदेश XVII नियम 2 सी. पी. सी. के स्पष्टीकरण को लागू करने में गंभीर त्रुटि की है। उनके अनुसार, मुकदमे को समाप्त करने का आदेश देते हुए निचली अदालत द्वारा पारित आदेश और 04.12.2004 दिनांकित पूर्व आदेश केवल आदेश XVII नियम 2 सी. पी. सी. के तहत एक आदेश था और स्पष्टीकरण के तहत नहीं था क्योंकि स्पष्टीकरण लागू नहीं होगा। यह भी प्रस्तुत किया गया था कि ट्रायल कोर्ट ने स्वयं मुकदमे का आदेश देते समय दर्ज किया था कि यह एक एक्सपार्ट डिक्री थी और ऑर्डर IX रूल 13 सी. पी. सी. के तहत एक एक्सपार्ट डिक्री को वापस लेने के लिए आवेदन किया जा सकता है।

12. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी एम. एस. ई. बी. के लिए विद्वान अधिवक्ता का निवेदन इस आशय का है कि उन निदेशकों में से केवल एक ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जबकि प्रतिवादी नं.1-कंपनी के साथ-साथ अन्य चार निदेशकों ने भी एन. ओ. एस. का प्रतिवाद किया। 2 से 4 और 6 इस न्यायालय के समक्ष उक्त आदेश को चुनौती नहीं दे रहे हैं। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय आदेश XVII नियम 2 सी. पी. सी. के स्पष्टीकरण का आह्वान करके रिट याचिका को अनुमति देने में सही था और अपील खारिज की जानी चाहिए।

13. यह उल्लेख करना सार्थक होगा कि इस न्यायालय ने दिनांक 1 के आदेश के माध्यम से अपीलार्थी को मुकदमे के दावे का 50 प्रतिशत यानी रु. 500 करोड़ का आधा जमा करने का निर्देश दिया था। 1,42,85,177/- छह सप्ताह की अवधि के भीतर और मामले को छह सप्ताह के बाद सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था। आई. डी. 1 पर, इस न्यायालय को यह संतुष्ट करते हुए कि मुकदमे के दावे का 50 प्रतिशत ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमा कर दिया गया है, निर्देश दिया कि ट्रायल कोर्ट उक्त राशि को शुरू में छह महीने की अवधि के लिए स्वचालित नवीनीकरण के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करेगा। इस न्यायालय ने आगे देरी को माफ कर दिया, प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किए और विवादित फैसले पर रोक लगा दी।

14. प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ने से पहले, आदेश XVII नियम 2 सी. पी. सी. को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो इस प्रकार है:

“2. प्रक्रिया यदि पक्ष दूसरे दिन उपस्थित होने में विफल रहते हैं।- कहाँ, पर

जिस दिन वाद की सुनवाई स्थगित की जाती है, पक्षकार या उनमें से कोई भी उपस्थित होने में विफल रहता है, उस दिन न्यायालय आदेश IX द्वारा उस ओर से निर्देशित तरीकों में से किसी एक में वाद का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ सकता है या ऐसा अन्य आदेश दे सकता है जो वह मानता है।

[2023] 11 एस सी आर।

स्पष्टीकरण।- जहां किसी भी पक्ष के साक्ष्य या साक्ष्य का एक बड़ा हिस्सा पहले ही दर्ज किया जा चुका है और ऐसा पक्ष किसी भी दिन पेश होने में विफल रहता है जिस दिन मुकदमे की सुनवाई स्थगित की जाती है, तो न्यायालय अपने विवेकाधिकार पर मामले में आगे बढ़ सकता है जैसे कि ऐसा पक्ष मौजूद था।”

15. यह आदेश IX नियम 13 को पुनः प्रस्तुत करने के लिए भी प्रासंगिक होगा जो इस प्रकार है:

“प्रतिवादी के खिलाफ डिक्री को अलग करना-किसी भी मामले में जिसमें

किसी प्रतिवादी के विरुद्ध एकतरफा डिक्री पारित की जाती है, वह उस न्यायालय में आवेदन कर सकता है जिसके द्वारा डिक्री पारित की गई थी, उसे दरकिनार करने के आदेश के लिए; और यदि वह न्यायालय को संतुष्ट करता है कि समन की विधिवत तामील नहीं की गई थी, या जब मुकदमा सुनवाई के लिए बुलाया गया था, तो उसे किसी पर्याप्त कारण से उपस्थित होने से रोका गया था, तो न्यायालय उसके खिलाफ डिक्री को ऐसी शर्तों पर दरकिनार करते हुए एक आदेश देगा जो वह लागत, न्यायालय में भुगतान या अन्यथा के बारे में सोचता है, और मुकदमे के साथ आगे बढ़ने के लिए एक दिन निर्धारित करेगा:

बशर्ते कि जहां डिक्री ऐसी प्रकृति की हो कि उसे केवल ऐसे प्रतिवादी के खिलाफ अलग नहीं किया जा सकता है, उसे सभी या किसी अन्य प्रतिवादी के खिलाफ भी अलग किया जा सकता है:

बशर्ते कि कोई भी न्यायालय एकतरफा पारित डिक्री को केवल इस आधार पर दरकिनार नहीं करेगा कि समन की सेवा में अनियमितता हुई है, यदि यह संतुष्ट होता है कि प्रतिवादी को सुनवाई की तारीख की सूचना मिली थी और उसके पास वादी के दावे का जवाब देने और पेश होने के लिए पर्याप्त समय था।स्पष्टीकरण-जहां इस नियम के तहत एकतरफा पारित डिक्री के खिलाफ अपील की गई है, और अपील का निपटारा इस आधार के अलावा किसी अन्य आधार पर किया गया है कि अपीलार्थी ने अपील वापस ले ली है, तो इस नियम के तहत एकतरफा डिक्री को रद्द करने के लिए कोई आवेदन नहीं होगा।”

16. आदेश IX नियम 13 के एक सादे पठन से यह स्पष्ट होता है कि जहां किसी मामले में, प्रतिवादी के खिलाफ एक तरफ से एक डिक्री पारित की जाती है, वहां एक पक्ष उपस्थित न होने के संबंध में न्यायालय को संतुष्ट करने वाले कारणों से उसे अलग करने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

17. आदेश XVII नियम 2 सी. पी. सी. पर आते हुए, यह स्पष्ट होगा कि यदि पक्षकार या उनमें से कोई एक उस दिन उपस्थित होने में विफल रहता है जिस दिन मुकदमे की सुनवाई

स्थगित की जाती है, तो न्यायालय एक 147 में मुकदमे का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ सकता है।

वाई. पी. लीले बनाम महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड [विक्रम नाथ, जे.]
148.

आदेश IX द्वारा उस ओर से निर्देशित विधियों का या ऐसा अन्य आदेश करें जो वह मानता है।

18. वर्तमान मामले में, प्रतिवादी 04.12.2004 पर उपस्थित नहीं हुए, और न ही उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए क्योंकि उन्होंने पहले ही एक लिखित अनुरोध द्वारा अपना वकालतनामा वापस ले लिया था। ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादियों के खिलाफ आदेश XVII नियम 2 सी. पी. सी. के तहत मुकदमा चलाने का निर्देश दिया। दिनांकित 04.12.2004 आदेश का प्रभाव यह था कि विचारण न्यायालय आदेश IX सी. पी. सी. द्वारा उस ओर से निर्देशित तरीकों में से एक में मुकदमे का निपटारा करने के लिए आगे बढ़ सकता था। सी. पी. सी. के आदेश IX पर वापस आते हुए, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इसके नियम 6 के तहत जहां समन विधिवत दिए जाते हैं और जब मुकदमा सुनवाई के लिए बुलाया जाता है तो प्रतिवादी उपस्थित नहीं होता है, तो अदालत एक आदेश दे सकती है कि मुकदमे की सुनवाई एकतरफा की जाए। यह वास्तव में वर्तमान मामले में निचली अदालत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया है। तदनुसार, वादी के साक्ष्य के समाप्त होने और प्रतिवादी के अनुपस्थित रहने के बाद, निचली अदालत ने दिनांक 29.01.2005 के फैसले के माध्यम से मुकदमे को एकतरफा फैसला सुनाया। इसके कार्यात्मक भाग में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि मुकदमा एकतरफा घोषित किया गया है।

19. अब स्पष्टीकरण पर आते हुए, उसमें जो कहा गया है वह यह है कि जहां किसी भी पक्ष के साक्ष्य या साक्ष्य का एक बड़ा हिस्सा पहले ही दर्ज किया जा चुका है और ऐसा पक्ष किसी भी दिन पेश होने में विफल रहता है जिस दिन मुकदमे की सुनवाई स्थगित की जाती है, तो न्यायालय मामले को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होगा जैसे कि ऐसा पक्ष मौजूद था। "किसी भी पक्ष" और "ऐसे पक्ष" की व्याख्या में दो वाक्यांश महत्वपूर्ण हैं। "कोई भी पक्ष" उस पक्ष को संदर्भित करता है जिसने साक्ष्य या पर्याप्त साक्ष्य का नेतृत्व किया है और "ऐसा पक्ष" उसी पक्ष को संदर्भित करता है जिसने साक्ष्य या पर्याप्त साक्ष्य का नेतृत्व किया है। यह स्पष्ट है कि आदेश XVII नियम 2 के तहत, न्यायालय किसी भी पक्ष के अनुपस्थित रहने या दोनों पक्षों के अनुपस्थित रहने के संबंध में आदेश पारित करने के लिए आगे बढ़ेगा। जबकि स्पष्टीकरण उस पक्ष और अकेले उस पक्ष की उपस्थिति को दर्ज करने के लिए माना जाता है, जिसने साक्ष्य या पर्याप्त साक्ष्य का नेतृत्व किया है और उसके बाद उपस्थित होने में विफल रहा है। वर्तमान मामले में, स्वीकार किया जाता है कि मुकदमा वादी के साक्ष्य के स्तर पर था जैसा कि दिनांकित 04.12.2004 आदेश से स्पष्ट है। प्रतिवादियों का साक्ष्य शुरू भी नहीं हुआ था और प्रतिवादियों के अधिवक्ता ने वादी के साक्ष्य की प्रतिपरीक्षा भी नहीं की थी। 20. वर्तमान मामले में स्पष्टीकरण केवल तभी दिया जा सकता था जब वादी, अपना साक्ष्य या पर्याप्त

साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद, उपस्थित होने में विफल रहा हो, अदालत अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकती थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 11 एस सी आर।

सूट का निपटान करना।लेकिन एक बार जब प्रतिवादी ने कोई सबूत नहीं दिया था, तो प्रतिवादी/अपीलार्थी के खिलाफ स्पष्टीकरण का आह्वान नहीं किया जा सका।उच्च न्यायालय ने आदेश XVII नियम 2 सी. पी. सी. के स्पष्टीकरण को लागू करने में एक त्रुटि की और इसके आधार पर कहा कि आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत एक आवेदन बनाए रखने योग्य नहीं होगा क्योंकि प्रतिवादी की उपस्थिति को मुकदमे के निपटारे के समय दर्ज किया गया माना जाएगा।21. वास्तव में, एक बार जब अधिवक्ता ने अपना वकालतनामा वापस ले लिया था, तो सामान्य रूप से, निचली अदालत को प्रतिवादियों को एक अन्य अधिवक्ता को शामिल करने के लिए नोटिस जारी करना चाहिए था, जो उसने नहीं किया और एकतरफा रूप से आगे बढ़ा।ट्रायल कोर्ट ने ऐसा करने में गलती की।इसके अलावा, निचली अदालत को अपने विवेक और विवेक से आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत आवेदन को अनुमति देने के बाद, उच्च न्यायालय को उस आदेश में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए था जो दोनों पक्षों को अवसर प्रदान करके न्याय के कारण को आगे बढ़ाता है ताकि मुकदमे का निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया जा सके।

22. ऊपर दर्ज सभी कारणों से, हम उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को बरकरार रखने में असमर्थ हैं।अपील की अनुमति है।उच्च न्यायालय के विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है।विचारण न्यायालय पक्षकारों को उचित अवसर देने के बाद अपने गुण-दोष के आधार पर विशेष दीवानी मुकदमे पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेगा और कानून के अनुसार सख्ती से आगे बढ़ेगा।

23. एक बार एकतरफा डिक्री को अलग कर दिए जाने के बाद, अपीलार्थी द्वारा जमा की गई 50 प्रतिशत राशि का उचित हिसाब रखा जाना चाहिए।यह सच है कि आदेश IX नियम 13 सी. पी. सी. के तहत, अदालत, आवेदन को अनुमति देते हुए, ऐसे नियम और शर्तें लागू कर सकती थी जो वह मानती है और यह एक धन डिक्री होने के कारण, निचली अदालत अपीलार्थी को कुछ राशि जमा करने के लिए कह सकती थी।अपीलार्थी प्रतिवादी सं. के उप निदेशकों में से एक है।1. यद्यपि दावा की गई राहत प्रत्येक निदेशक के संयुक्त और कई दायित्वों के लिए थी, हमारे विचार में उपरोक्त अपीलार्थी के हाथों 50 प्रतिशत की जमा राशि बहुत अधिक होगी।तदनुसार हम यह प्रावधान करते हैं कि इस न्यायालय के आदेश के तहत अपीलार्थी द्वारा जमा की गई राशि, जो विचारण न्यायालय में है, को निम्नानुसार समायोजित किया जा सकता है:

(i) वाद दावे का 20 प्रतिशत, उस पर उपार्जित ब्याज के साथ, विचारण न्यायालय द्वारा बरकरार रखा जा सकता है और इसे शुरू में छह महीने की अवधि के लिए सावधि जमा में जमा करना जारी रख सकता है।

वाई. पी. लीले बनाम महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड [विक्रम नाथ, जे.]

स्वचालित आधार पर नवीनीकरण, जब तक कि मुकदमे के परिणाम के आधार पर उस संबंध में आगे के आदेश पारित नहीं किए जाते;

((ख)) जबकि 30 प्रतिशत, उस पर उपार्जित ब्याज के साथ, निचली अदालत के समक्ष इस आदेश के लागू होने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर अपीलार्थी को राशि की वापसी के लिए एक आवेदन के साथ वापस किया जा सकता है जैसा कि ऊपर निर्देश दिया गया है।

24. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

25. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोट:

अपील की अनुमति दी गई।

अंकित ज्ञान